



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 अक्टूबर, 2024

आश्विन 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 34/705/सात-न्याय-2-2024-216-77

लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-279

चूँकि अधिसूचना संख्या 1002/सात-न्याय-2-06-216-77, दिनांक 22 सितम्बर, 2006, द्वारा जिले में तैनात द्वितीय ज्येष्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सरकारी अधिसूचना संख्या 804/सात-न्याय-2-2001-216-77, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के अधीन गठित सहकारी समितियों में गबन से संबंधित मामलों के विनिश्चय हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था।

अतएव अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2024) की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति से इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

अधिसूचना संख्या 1002/सात-न्याय-2-06-216-77, दिनांक 22 सितम्बर, 2006, में शब्द "द्वितीय ज्येष्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "द्वितीय ज्येष्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और जहां द्वितीय ज्येष्ठतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय विद्यमान नहीं है या रिक्त है, वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय" रख दिये जायेंगे।

2-तदनुसार अधिसूचना संख्या 1002/सात-न्याय-2-06-216-77, दिनांक 22 सितम्बर, 2006 को पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,
विनोद सिंह रावत,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 34/705/VII- Nyaya-2-2024-216-77, dated October 9, 2024 for general information :

No. 34/705/VII- Nyaya-2-2024-216-77

Dated Lucknow, October 9, 2024

WHEREAS *vide* notification no. 1002/VII-Nyaya-2/06-216-77, dated September 22, 2006, Court of the second senior-most Additional Chief Judicial Magistrate posted in the district was designated as Special Court for deciding cases relating to embezzlement in Co-operative Societies constituted under the Government notification no. 804/VII-Nyaya-2-2001/216-77, dated September 28, 2001;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2024) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad with effect from the date of publication of this notification in the official *Gazette*, is pleased to make the following amendment in the aforesaid notification,—

AMENDMENT

IN notification no. 1002/VII-Nyaya-2/2006-216-77, dated September 22, 2006 for the words "**second senior most Additional Chief Judicial Magistrate**", the words "**Court of the second senior most Additional Chief Judicial Magistrate; and where the Court of the second second most Additional Chief Judicial Magistrate does not exist or is vacant, Court of the Chief Judicial Magistrate**" shall be *substituted*.

2. Accordingly, notification no. 1002/VII-Nyaya/2-2006-216-77, dated September 22, 2006 shall be deemed to have been amended to the aforesaid extent.

By order,
VINOD SINGH RAWAT,
Pramukh Sachiv.

